



फॉस्फोरस बम

प्रलिम्स के लिये:

फॉस्फोरस बम, डोनबास क्षेत्र, रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी), ऑस्ट्रेलिया समूह।

मेन्स के लिये:

महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, रूस-यूक्रेन युद्ध।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूक्रेन की पुलिस द्वारा रूसी सेना पर आरोप लगाया गया है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के लुगांसक और डोनेट्सक क्षेत्रों, जिन्हें सामूहिक रूप से डोनबास (Donbas) के रूप में जाना जाता है, में फॉस्फोरस बम (रासायनिक हथियार) से हमले किये हैं।

- अंतरराष्ट्रीय कानून अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में सफेद/हवाइड फॉस्फोरस के बम के उपयोग को प्रतिबंधित करता है लेकिन खुले स्थानों पर सैनिकों को कवर/सुरक्षा प्रदान करने के लिये इनके इस्तेमाल की अनुमति देता है।

प्रमुख बंदी

फॉस्फोरस बम:

- एलोट्रोप्स/अपरूप:** सफेद फॉस्फोरस एक ऐसा युद्धक हथियार है जिसमें रासायनिक तत्त्व फॉस्फोरस के किसी अपरूप (Allotropes) का उपयोग किया जाता है।
- पायरोफोरिक:** सफेद फॉस्फोरस एक स्वतः ज्वलनशील/पायरोफोरिक (Pyrophoric) तत्त्व है (यह हवा के संपर्क में आने पर प्रज्वलित होता है), यह अत्यधिक ज्वलनशील है जो कपड़ा, ईंधन, गोला-बारूद और अन्य ज्वलनशील पदार्थों को प्रज्वलित कर सकता है।
 - इसके अलावा इसका उपयोग ट्रेसर गोला बारूद (Tracer Ammunition) में रोशनी युक्त धुआँ उत्पादन करने और ज्वलनशील तत्त्वों के रूप में भी किया जाता है।
- रासायनिक प्रतिक्रिया:** अपनी आक्रामक क्षमताओं के अलावा सफेद फॉस्फोरस एक अत्यधिक तीव्र धुआँ-उत्पादक एजेंट (Smoke-Producing Agent) है, जो हवा के साथ प्रतिक्रिया करके तत्काल वषिकृत फॉस्फोरस पेंटोक्साइड वाष्प (Phosphorus Pentoxide Vapour) के आवरण का निर्माण करता है।
- प्रभाव:** फॉस्फोरस से निर्मित पेंटोक्साइड वाष्प के आवरण के टुकड़ों की वजह से गंभीर चोटों के अलावा सफेद फॉस्फोरस युद्ध सामग्री मुख्य तौर पर दो तरीकों से नुकसान पहुँचाने का कारण बन सकती है: जलने और वाष्प में साँस लेने से।

रासायनिक हथियार:

- रासायनिक हथियार एक ऐसा रसायन होता है जिसका उपयोग इसके ज़हरीले गुणों के माध्यम से जान-बूझकर मौत या नुकसान पहुँचाने के लिये किया जाता है।
- वर्ष 1918 से ज़हरीले रसायनों से हथियार बनाने के लिये डिज़ाइन की गई युद्ध सामग्री, उपकरण और अन्य हथियार भी रासायनिक हथियारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

रासायनिक हथियारों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय कानून:

- रासायनिक हथियार कन्वेंशन (Chemical Weapons Convention- CWC) रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने और निर्धारित समय के भीतर उनके वनिश हेतु एक बहुपक्षीय संधि है।
- CWC के लिये वार्ता की शुरुआत वर्ष 1980 में नरिसत्त्रीकरण को लेकर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शुरू हुई।
- इस कन्वेंशन का मसौदा सितंबर 1992 में तैयार किया गया था और जनवरी 1993 में इसे हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत किया गया था। यह अप्रैल

1997 से प्रभावी हुआ।

- यह पुराने और प्रयोग किये जा चुके रासायनिक हथियारों को नष्ट करना अनिवार्य बनाता है।
- सभी सदस्य देशों को उनके पास मौजूद दंगा नरियंत्रण एजेंट (यानी 'ऑसू गैस' आदि) के वषिय में भी घोषणा करनी चाहिये।
- भारत ने जनवरी 1993 में संधिपर हस्ताक्षर किये। रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम, 2000 CWC को लागू करने हेतु पारति कया गया था।
- यह कन्वेंशन प्रतबंधित करता है:
 - रासायनिक हथियारों का विकास, उत्पादन, अधगिरहण, भंडारण या प्रतधारण।
 - रासायनिक हथियारों का स्थानांतरण।
 - रासायनिक हथियारों का उपयोग करना।
 - CWC द्वारा नषिदिध गतविधियों में शामिल होने के लयि अन्य पक्षों की सहायता करना।
 - दंगा नरियंत्रण उपकरणों का उपयोग 'युद्ध सामग्री' के रूप में करना।
- CWC के अलावा 'ऑस्ट्रेलिया समूह' रासायनिक या जैविक हथियारों के प्रसार को भी रोकता है।

‘ऑस्ट्रेलिया समूह’ क्या है?

- ऑस्ट्रेलिया समूह (AG) देशों का एक अनौपचारिक मंच है, जो कसिी भी ऐसी सामग्री के नरियात को नरियंत्रित कर यह सुनिश्चित करता है कि इसका उपयोग रासायनिक या जैविक हथियारों के विकास में न कया जाए।
- वर्ष 1985 में ऑस्ट्रेलिया समूह (AG) का गठन ईरान-इराक युद्ध (1980-1988) के दौरान इराक द्वारा रासायनिक हथियारों के उपयोग से प्रेरति था।
- राष्ट्रीय नरियात नरियंत्रण उपाय ऑस्ट्रेलिया समूह के सदस्यों को रासायनिक हथियार कन्वेंशन और जैविक एवं वषिकृत हथियार कन्वेंशन के तहत अपने दायतियों को पूरा करने में सहायता करते हैं।
- इसमें यूरोपीय संघ सहति 43 सदस्य हैं। सदस्य सर्वसम्मति के आधार पर काम करते हैं। इसकी वार्षिक बैठक पेरसि (फ्रांस) में आयोजति की जाती है।
- भारत 19 जनवरी, 2018 को ऑस्ट्रेलिया समूह में (43वें प्रतभागी के रूप में) शामिल हुआ था।
- 'ऑस्ट्रेलिया समूह' ने सर्वसम्मति से भारत को सदस्य के रूप में स्वीकार करने का नरिणय लया।

वगित वर्षों के प्रश्न

प्र. नमिनलखिति युगमों पर वचारि कीजयि: (2020)

अंतरराष्ट्रीय समझौता/सेट-अप	वषिय
1. अलमा-अता की घोषणा	: लोगों की स्वास्थय देखभाल
2. हेग कन्वेंशन	: जैविक और रासायनिक हथियार
3. तालानोआ संवाद	: वैश्विक जलवायु परिवर्तन
4. अंडर-2 गठबंधन	: बाल अधिकार

उपर्युक्त युगमों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: c

स्रोत: द हट्टि

MSMEs में NPA की बढ़ोतरी

प्रलिमिंस के लयि:

MSME और संबधति योजनाएँ।

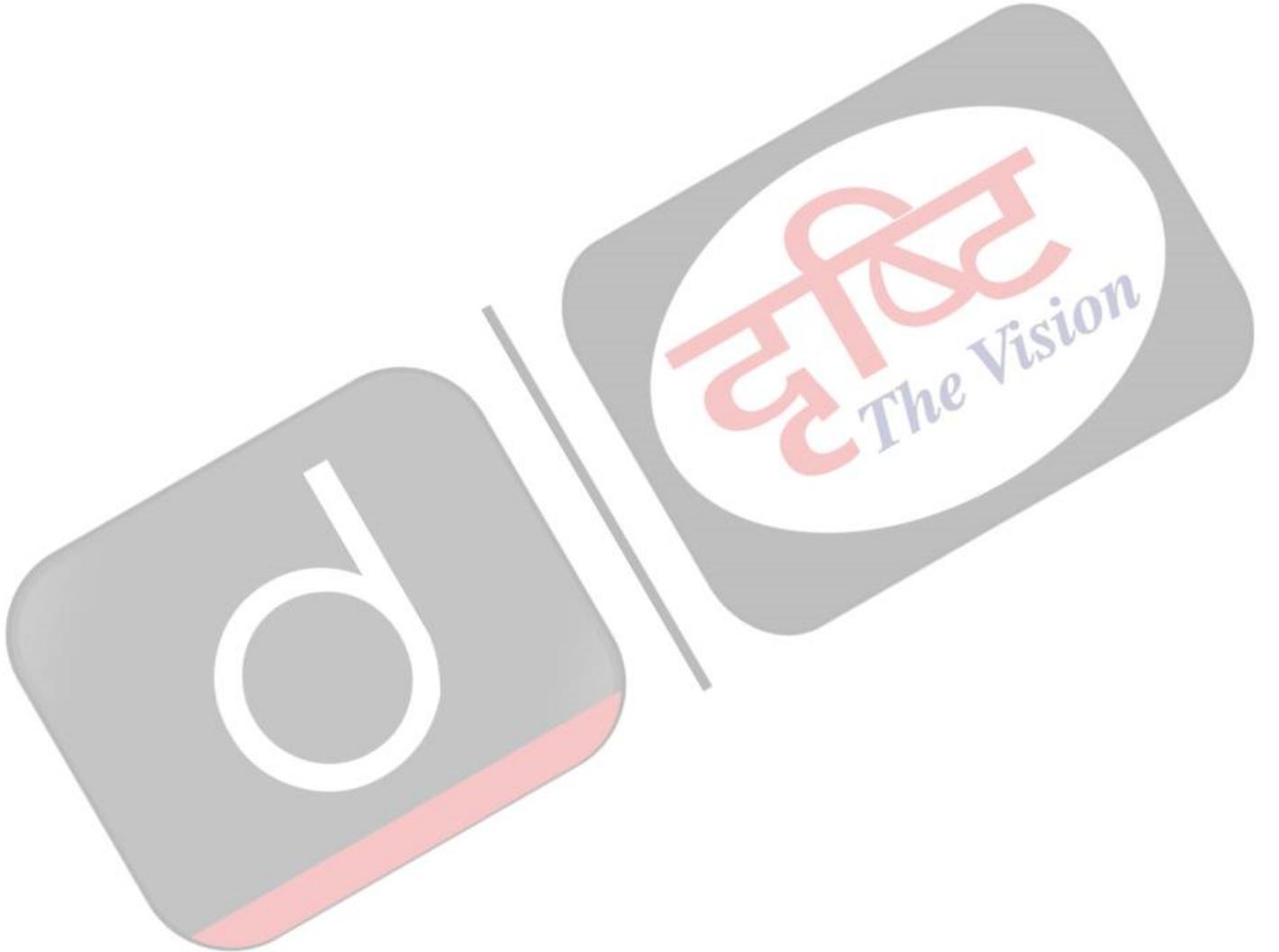
मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, MSMEs क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

[भारतीय रजिस्ट्रार बैंक](#) (RBI) और सरकार द्वारा घोषित कई ऋण पुनर्गठन योजनाओं और पैकेजों के बावजूद कोविड महामारी ने [‘सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों’](#) (MSMEs) को बहुत अधिक प्रभावित किया है।

- MSMEs की सकल गैर-नष्टिपादित परसिंपत्तियाँ (NPAs) या इन उद्यमों द्वारा डफ़ॉल्ट किये गए ऋण, सितंबर 2021 तक 20,000 करोड़ रुपए बढ़कर 1,65,732 करोड़ रुपए का हो गया, जो सितंबर 2020 में 1,45,673 करोड़ रुपए था।
- MSMEs के [‘बैड लोन’](#) अब 17.33 लाख करोड़ रुपए के ‘सकल अग्रिम’ (Gross Advances) का 9.6% है, जबकि सितंबर 2020 में यह 8.2% था।
- इससे पहले MSME मंत्रालय ने ‘MSME IDEA HACKATHON 2022’ के साथ [‘एमएसएमई इनोवेटिवि स्कीम’](#) (इनक्यूबेशन, डिज़ाइन और IPR) लॉन्च की थी।



गैर-नष्पादति परसिंपत्तक्या है?

- NPA उन ऋणों या अग्रमिों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है, जो डफिॉल्ट हो जाते हैं या जनिके मूलधन या ब्याज़ का अनुसूचति भुगतान बकाया होता है।
- अधिकतर मामलों में ऋण को गैर-नष्पादति के रूप में तब वर्गीकृत कया जाता है, जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दनिों की अवधि के लयि न कया गया हो।
- शुद्ध गैर-नष्पादति परसिंपत्तक्यिों वह राशरि है जो सकल गैर-नष्पादति परसिंपत्तक्यिों से 'प्रोवज़िन अमाउंट' की कटौती के बाद प्राप्त होती है।

MSMEs पर कोवडि-19 का प्रभाव:

- 'बैड लोन' में वृद्धरिज़रिर्व बैंक द्वारा जनवरी 2019, फरवरी 2020, अगस्त 2020 और मई 2021 में MSMEs के लयि घोषति चार ऋण पुनर्रगठन योजनाओं के बाद भी हुई।
 - इन योजनाओं के तहत 1,16,332 करोड़ रुपए के 24.51 लाख MSMEs खातों के ऋणों का पुनर्रगठन कया गया। रज़रिर्व बैंक की ओर से जारी मई 2021 के सर्कुलर के तहत 51,467 करोड़ रुपए के ऋणों का पुनर्रगठन कया गया।
- महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावति क्षेत्रों में से एक होने के कारण सरकार द्वारा मार्च 2020 में कोवडि महामारी के मद्देनज़र देशव्यापी सख्त लॉकडाउन की घोषणा के बाद हज़ारों MSMEs या तो बंद हो गए या उनकी आर्थकि स्थति खराब हो गई।

MSMEs की स्थति में सुधार हेतु कयि गए प्रयास:

- MSMEs की आर्थकि स्थति में सुधार करने हेतु रज़रिर्व बैंक और सरकार ने [आपातकालीन करेडिट लाइन गारंटी योजना](#) (ECLGS) सहति कई उपाय पेश कयि, जसिके तहत MSMEs और व्यवसायों को 3 लाख करोड़ रुपए का असुरकषति ऋण प्रदान कया गया।
- रज़रिर्व बैंक ने MSMEs को परसिंपत्तक्यिीकरण डाउनग्रेड के बनिा ऋण के एकमुश्त पुनर्रगठन की योजना का लाभ उठाने की अनुमति दी और साथ ही कृषि, एमएसएमई व आवास क्षेत्र को ऋण देने हेतु [NBFCs](#) (गैर बैंकिग वतितीय कंपनयिों-एमएफआई के अलावा) को अनुमति दी।
- हालाँकि इन पुनर्रगठन योजनाओं और पैकेजों से उन हज़ारों इकाइयों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ, जो पहले से ही डफिॉल्ट थीं।
- ऐसा इसलयि है, क्यौंकि ECLGS योजना के तहत पात्र होने के लयि उधारकर्त्ता का बकाया 29 फरवरी, 2020 तक 60 दनिों से कम या 60 दनिों तक का होना चाहयि।
 - [रज़रिर्व बैंक की वतितीय स्थरिता रिपीरट](#) के अनुसार, मार्च 2021 की तुलना में सतिंबर 2021 के अंत तक MSME सेगमेंट में ऋण (वर्ष-दर-वर्ष) कम हो गया।

NPA/बैड लोन से संबंधति कानून और प्रावधान:

- [सर्फेसी अधनियिम, 2002](#)
- [दविला और दविलयिापन संहति \(IBC\)](#)
- [बैड बैंक](#)

वगित वर्षों के प्रश्न

नमिनलखिति में से कौन समावेशी वकिस के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है? (2011)

1. स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना
2. सूकषम, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना
3. शकिषा का अधिकार अधनियिम को लागू करना

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: d

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल

प्रलिस के लयऱः

पीएम गतऱ शक्तऱ यऱजना, राषुटरीय अवसंरचना पाइपलाइन ।

मेनुस के लयऱः

संसाधनुं का संग्रहण, सरकारी बजट, राजकोषीय नीतऱ, सरकारी नीतयऱँ और हसुतकषेप, पीएम गतऱ शक्तऱ यऱजना का महतुतुव ।

चरुचा में कुयऱँ?

हाल ही में प्रधानमंतुरी के वजुन ["गतऱ शक्तऱ"](#) (Gati Shakti) के अनुरूप भारतीय रेल का पहला गतऱ शक्तऱ कार्गो टर्मिनल (Gati Shakti Cargo Terminal-GCT) पूरुवी रेलवे के आसनसोल मंडल (Asansol Division) में शुरु कयऱा गया है ।

- दसऱंबर '2021 में GCT नीतऱके लागू होने बाद से यह भारतीय रेलवे में इस तरह का पहला शक्तऱ कार्गो टर्मिनल है ।
- इससे भारतीय रेलवे की कुमाई में इजुाफा होने की उम्मीद है । इस टर्मिनल और अनुय ऐसे टर्मिनलस के चालू होने से देश की अरुथवुयवसुथा पर सकारातुमक प्रभाव पड़ेगा ।

प्रमुख बढऱः

प्रधानमंतुरी गतऱ शक्तऱ यऱजना:

- प्रधानमंतुरी गतऱ शक्तऱ यऱजना के बारे में:
 - वर्ष 2021 में भारत सरकार ने लऱजसुटकुस लागत को कुम करने के लयऱः समनुवतऱ और बुनयऱदी अवसंरचना परयऱोजनाओं के नषुपादन हेतु महतुतुवाकांकषी गतऱ शक्तऱ यऱजना या 'नेशनल मासुटर प्लान फऱर मलुटी-मऱडल कनेकुटवऱडऱ प्लान' लऱनुच कयऱा है ।
- उदुदेशुय:
 - जुमीनी सुतर पर कारुय में तेजुी लाने, लागत को कुम करने और रऱजगार सृजन पर धुयान देने के साथ-साथ आगामी चार वर्षों में बुनयऱदी अवसंरचना परयऱोजनाओं की ँकीकृत यऱजना और कारुयानुवयन सुनशुचऱतऱ करना ।
 - गतऱ शक्तऱ यऱजना के तहत वर्ष 2019 में शुरु की गई 110 लाख कुरोडु रुपँ की ["राषुटरीय अवसंरचना पाइपलाइन"](#) को शामिल करना ।
 - लऱजसुटकुस लागत में कुटऱुती के अलावा इस यऱजना का उदुदेशुय कारुगु हैडलगऱ कुषमता को बढुाना और वुयऱपार को बढुावा देने हेतु बंदरगाहों पर टरनुअराउंड समय को कुम करना है ।
 - इसका लकुषुय 11 [ऱुदुयऱगकु गलुयऱरे](#) और दु नँ [रकुषा गलुयऱरे](#) (ँक तमलऱनाडु में और दुसरा उतुतर प्रदेश में) बनाना भी है ।
 - इसके तहत सभी गाँवों में 4G कनेकुटवऱडऱ का वसुतऱार कयऱा जऱँगा । साथ ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 कलऱमीटर की कुषमता जुडुने की यऱजना बनाई जा रही है ।
 - यह वर्ष 2024-25 के लयऱः सरकार दुवऱरा नरुधऱरतऱ महतुतुवाकांकषी लकुषुयों को पूरा करने में मदद करेगा, जसुमें राषुटरीय राजमऱर्ग नेटवर्क की लंबाई को 2 लाख कलऱमीटर तक वसुतऱारतऱ करना, 200 से अधकु नँ हवाई अडुडुओं, हेलऱपऱरुट और वाटर ँयरोडुरोम का नरुमाण करना शामिल है ।



■ अपेक्षित परिणाम:

- यह योजना मौजूदा और प्रस्तावित कनेक्टविटी परियोजनाओं की मैपिंग में मदद करेगी।
- साथ ही इसके माध्यम से देश में विभिन्न क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने संबंधी योजना भी स्पष्ट हो सकेगी।
- यह समग्र एवं एकीकृत परिवहन कनेक्टविटी रणनीति 'मेक इन इंडिया' का समर्थन करेगी और परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करेगी।
- इससे भारत को विश्व की व्यापारिक राजधानी बनने में मदद मिलेगी।

■ एकीकृत बुनियादी अवसंरचना के विकास की आवश्यकता:

- समन्वय एवं उन्नत सूचना साझाकरण की कमी के कारण वृहतस्तरीय नियोजन और सूक्ष्म स्तरीय कार्यान्वयन के बीच एक व्यापक अंतर मौजूद है, क्योंकि विभाग प्रायः अलगाव की स्थिति में कार्य करते हैं।
- एक अध्ययन के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13% है, जो विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है।
 - इस उच्च लॉजिस्टिक लागत के कारण भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बहुत कम हो जाती है।
- विश्व स्तर पर यह स्वीकार किया जाता है कि सतत विकास के लिये गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अवसंरचना का निर्माण काफी महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से व्यापक पैमाने पर रोजगार पैदा करता है।
- इस योजना का कार्यान्वयन 'राष्ट्रीय मुद्रांकन पाइपलाइन' (NMP) के साथ समन्वय स्थापित कर किया जाएगा।
 - 'राष्ट्रीय मुद्रांकन पाइपलाइन' को मुद्रांकन हेतु एक स्पष्ट ढाँचा प्रदान करने और संभावित निवेशकों को बेहतर रिटर्न की प्राप्ति के लिये संपत्तियों की एक सूची निर्दिष्ट करने हेतु शुरू किया गया है।

संबद्ध चर्चाएँ:

- **लो क्रेडिट ऑफ-टेक:** हालाँकि सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिये कई सुधार किये हैं और [दवाला एवं दवालयुक्त संहिता](#) ने खराब ऋणों पर लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए की वसूली की, इसके बावजूद ऋण लेने की प्रवृत्ति में गतिरोध को लेकर चर्चा व्यक्त की गई है।
 - भविष्य की आय और मौजूदा बाजार के प्रमाण के माध्यम से भविष्य की परियोजनाओं के वित्तपोषण में व्यवसायों की मदद करने के लिये बैंक क्रेडिट ऑफ-टेक की सुविधा देते हैं।
- **मांग में कमी:** कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में निजी मांग और निवेश की कमी देखी गई है।
- **संरचनात्मक समस्याएँ:** भूमि अधिग्रहण में देरी और मुकदमेबाजी के मुद्दों के कारण देश में वैश्विक मानकों की तुलना में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दर बहुत धीमी है।
 - इसके अतिरिक्त भूमि प्रयोग और पर्यावरण मंजूरी के मामले में विलंब, अदालत में लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे आदि अवसंरचना परियोजनाओं में देरी के कुछ प्रमुख कारण हैं।

आगे की राह

- PM गति शक्ति सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। हालाँकि इसके उच्च सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न संरचनात्मक और व्यापक आर्थिक स्थिरता संबंधी चर्चाओं को दूर करने की आवश्यकता है।
 - इस प्रकार आवश्यक है कि यह पहल एक स्थिर और पूर्वानुमेय नियामक एवं संस्थागत ढाँचे पर आधारित हो।

वर्षों के प्रश्न:

प्र. हाल ही में भारत का पहला 'राष्ट्रीय निवेश और निरिमाण क्षेत्र' कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था? (2016)

- (a) आंध्र प्रदेश
- (b) गुजरात
- (c) महाराष्ट्र
- (d) उत्तर प्रदेश

उत्तर: (a)

स्रोत: पी.आई.बी.

नदियों के कायाकल्प पर वस्तुतः परियोजना रिपोर्ट

प्रलिमिस के लिये:

नदियों के कायाकल्प पर वसित्त परियोजना रिपोर्ट, शुद्ध शून्य उत्सर्जन, 2070 तक भारत का शुद्ध शून्य लक्ष्य, कोप-26, अक्षय ऊर्जा लक्ष्य।

मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप, नदियों के कायाकल्प पर वसित्त परियोजना रिपोर्ट के लाभ और संबंधित चुनौतियाँ।

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) द्वारा संयुक्त रूप से वानिकी संबंधी पहलों के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर वसित्त परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report- DPR) जारी की गई है।

- 13 प्रमुख नदियों में झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी शामिल हैं।

प्रमुख बंदी

DPRs के पीछे का विचार:

- इसे वर्ष 2015-16 में [राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन](#) (National Mission for Clean Ganga- NMCG) के हिस्से के रूप में किये गए कार्यों की तर्ज पर यह स्वीकार करते हुए तैयार किया गया है कि बढ़ता जल संकट नदी के पारस्थितिक तंत्र के क्षरण का कारण है।
- यह परियोजना रिपोर्ट एक बहु-स्तरीय, बहु-हतिधारक, बहु-वषियक और समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है ताकि 'अवरिल धारा' (Uninterrupted Flow), 'नरिमल धारा' (Clean Water) और पारस्थितिक कायाकल्प के व्यापक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

शामल क्षेत्र/परदृश्य:

- 13 नदियों सामूहिक रूप से 18,90,110 वर्ग कमी. के कुल बेसिन क्षेत्र को आच्छादित करती हैं जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 57.45 फीसदी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
- परियोजना के अंतर्गत 202 सहायक नदियों सहित 13 नदियों की कुल लंबाई 42,830 कमी. है।
 - ब्रह्मपुत्र रविरक्षेप में सर्वाधिक सहायक नदियाँ (30) और 1,54,456 वर्ग कमी. का क्षेत्र शामिल हैं।
- दस्तावेजों में नदियों के परदृश्य में वानिकी पहलों का प्रस्ताव किया गया है जिसमें लकड़ी की प्रजातियाँ, औषधीय पौधों, घास, झाड़ियों व ईंधन, चारा और फलों वाले पेड़ों सहित वानिकी वृक्षारोपण के विभिन्न मॉडलों द्वारा जल सत्र को बढ़ाना, भूजल में वृद्धि के साथ ही क्षरण को रोकना शामिल है।

नयोजित हस्तक्षेप:

- DPR तीन प्रकार के परदृश्यों में वानिकी हस्तक्षेप और आर्द्रभूमि प्रबंधन के लिये एक समग्र रविरक्षेप दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता की पहचान करती है।
- ये कार्य नीति स्तरीय हस्तक्षेप, रणनीतिक और अनुकूल अनुसंधान, क्षमता विकास, जागरूकता निर्माण, परियोजना प्रबंधन एवं भागीदारी निगरानी तथा मूल्यांकन जैसी सहायक गतिविधियों के साथ किये जाते हैं।

प्रस्तावित हस्तक्षेपों के संभावित लाभ:

- वन आवरण में वृद्धि:**
 - इससे 13 नदियों के परदृश्य में 7,417.36 वर्ग कमी. के संचयी वन क्षेत्र में वृद्धि होने की संभावना है।
- CO₂ के पृथक्करण में सहायता:**
 - प्रस्तावित हस्तक्षेप से 10 साल पुराने वृक्षारोपण से 50.21 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड और 20 साल पुराने वृक्षारोपण से 74.76 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में मदद मिलेगी।
- भूजल पुनर्भरण में सहायता:**
 - वे भूजल पुनर्भरण में मदद के साथ अवसादन को कम करेंगे, इसके अलावा गैर-लकड़ी और अन्य वन उपज से 449.01 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है।
- रोज़गार सृजन:**
 - उनसे लगभग 344 मिलियन मानव-दिवस कार्य के माध्यम से रोज़गार सृजन की दृष्टि में महत्वपूर्ण योगदान की भी संभावना है।
- अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना:**
 - इन प्रयासों से भारत को अपनी अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी:
 - [संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज](#) (यूएनएफसीसीसी) के [पेरिस समझौते](#) के तहत वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन CO₂ समकक्ष का एक अतिरिक्त कार्बन सिक बचाना;
 - वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब पड़ी भूमि को पुनर्स्थापित करना।

- **कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी** (सीबीडी) और सतत् विकास लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना।
- **COP-26** में भारत ने वर्ष 2030 तक अपने अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन कम करने, वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा के माध्यम से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने, इसकी कार्बन तीव्रता को कम करने एवं वर्ष 2030 तक 45% अर्थव्यवस्था और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का वादा किया।
- **बॉन चैलेंज** के तहत भारत ने वर्ष 2015 में वर्ष 2030 तक 50 लाख हेक्टेयर नमिनीकृत भूमिको बहाल करने का भी वादा किया था।

वर्षों के प्रश्न

'मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है? (2018)

- (a) जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल
- (b) यूएनईपी सचिवालय
- (c) यूएनएफसीसीसी सचिवालय
- (d) विश्व मौसम विज्ञान संगठन

उत्तर: c

संबंधित चुनौतियाँ

- नदी पारस्थितिक तंत्र के सिकुड़ने और क्षरण के कारण पीने योग्य जल संसाधनों के घटने से बढ़ता जल संकट पर्यावरण, संरक्षण, जलवायु परिवर्तन व सतत् विकास से संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है।
- परियोजना की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है, जसमें वृक्षारोपण की सही विधि और जलवायु में परिवर्तन शामिल हैं।

आगे की राह

- वृक्षारोपण के जोखिमों एवं जलवायु में परिवर्तन से बचने के लिये वन विभाग को 'रोपण स्टॉक की गुणवत्ता, विशेष रूप से आयु एवं आकार जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा, साथ ही जोखिम को और कम करने के लिये वृक्षारोपण से पहले मिट्टी एवं नमी का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है।

वर्षों के प्रश्न

नमिनलखिति में से कौन 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (NGRBA) की प्रमुख विशेषताएँ हैं? (2016)

1. नदी बेसिन, नियोजन एवं प्रबंधन की इकाई है।
2. यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण के प्रयासों का नेतृत्व करता है।
3. उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक जसि राज्य से गंगा बहती है, चक्रानुक्रम के आधार पर NGRBA के अध्यक्ष बनते हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

स्रोत: पी.आई.बी.

फ्लड प्लेन ज़ोनगि

परलिमिस के लयि:

फ्लड प्लेन ज़ोनगि, बाढ़, भारत की बाढ़ के प्रतसिंवेदनशीलता ।

मेन्स के लयि:

आपदा प्रबंधन, फ्लड प्लेन ज़ोनगि के लयि मॉडल बलि की चुनौतयिँ ।

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचति कयि है किमिणपुरि, राजस्थान, उत्तराखंड और तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्यों ने फ्लड प्लेन ज़ोनगि नीतिलागू की थी ।

- हालाँकि बाढ़ के मैदानों का परसिमन और सीमांकन कयि जाना बाकी है ।
- इससे पहले [भारत के नयित्तरक एवं महालेखा परीकषक \(CAG\)](#) ने केरल वधिनसभा में बाढ़ की तैयारी और प्रतकिरयि पर एक रपौरट पेश की ।
 - रपौरट में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को फ्लड प्लेन ज़ोनगि कानून के लयि एक मॉडल ड्राफ्ट बलि परचालति कयि जाने के 45 वर्ष बाद राज्यों ने अभी तक फ्लड प्लेन ज़ोनगि कानून नहीं बनाया है ।



फ्लड प्लेन ज़ोनगि:

परिचय:

- फ्लड प्लेन ज़ोनगि को बाढ़ प्रबंधन के लिये एक प्रभावी गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में मान्यता दी गई है।
- फ्लड प्लेन ज़ोनगि की मूल अवधारणा का उद्देश्य बाढ़ से होने वाले नुकसान को सीमित करने के लिये बाढ़ के मैदानों में भूमि उपयोग को वनियमिति करना है।

वशिष्टताएँ:

- वकिसात्मक गतविधियों का नरिधारण:** इसका उद्देश्य वकिसात्मक गतविधियों के लिये स्थानों और क्षेत्रों की सीमा को इस तरह से नरिधारति करना है कि नुकसान कम-से-कम हो।
- सीमाओं का नरिधारण:** इसमें असुरक्षति और संरक्षति दोनों क्षेत्रों के वकिसा पर सीमाएँ नरिधारति करने की परकिलपना की गई है।
 - असंरक्षति क्षेत्रों में अंधाधुंध वकिसा को रोकने के लिये जनि क्षेत्रों में वकिसात्मक गतविधियों पर प्रतबिंध लगाया जाएगा, उनकी सीमाएँ नरिधारति की जानी हैं।
 - संरक्षति क्षेत्रों में केवल ऐसी वकिसात्मक गतविधियों को अनुमति दी जा सकती है, जनिमें सुरक्षात्मक उपाय वफिल होने की स्थिति में भारी क्षति शामिल नहीं होगी।
- उपयोगिता:** ज़ोनगि मौजूदा स्थितियों का समाधान नहीं कर सकता है, हालाँकि यह नश्चिती रूप से वकिसा कार्यों में बाढ़ के कारण होने वाली क्षति को कम करने में मदद करेगा।
 - फ्लड-प्लेन ज़ोनगि न केवल नदियों द्वारा आने वाली बाढ़ के मामले में आवश्यक है, बल्कि यह वशिष रूप से शहरी क्षेत्रों में जल जमाव से होने वाले नुकसान को कम करने में भी उपयोगी है।

बाढ़ के प्रतसिंवेदनशीलता की भारत की स्थिति:

- भारत के उच्च जोखमि और भेद्यता को इस तथ्य से आकलति कया गया है कि 3290 लाख हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र में से 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र है।
- बाढ़ के कारण प्रतविरष औसतन 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावति होती है तथा लगभग 1600 लोगों की मृत्यु हो जाती है एवं इसके कारण फसलों व मकानों तथा जन-सुवधियों को होने वाली क्षति 1805 करोड़ रुपए की है।

फ्लड-प्लेन ज़ोनगि के लिये मॉडल ड्राफ्ट बलि:

- परिचय:** यह बलि/वधियक बाढ़ क्षेत्र प्राधकिरण, सर्वेक्षण और बाढ़ के मैदानी क्षेत्र के परसीमन, बाढ़ के मैदानों की सीमाओं की अधसूचना, बाढ़ के मैदानों के उपयोग पर प्रतबिंध, मुआवज़े व सबसे महत्वपूर्ण रूप से जल के मुक्त प्रवाह को सुनश्चिती करने के लिये इन बाधाओं को दूर करने के बारे में प्रवषिटि प्रदान करता है।
 - इसके तहत बाढ़ प्रभावी क्षेत्रों के नचिले इलाकों के आवासों को पार्कों और खेल मैदानों में प्रतस्थापति कया जाएगा क्योंकि उन क्षेत्रों में मानव बस्ती की अनुपस्थिति की वजह से जान-माल की हानि में कमी आएगी।
- कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:**
 - संभावति वधायी प्रकरिया के साथ-साथ बाढ़ के मैदानों के प्रबंधन हेतु वभिन्नि पहलुओं का पालन करने के दृष्टिकोण से राज्यों की ओर से प्रतरीध कया गया है।
 - राज्यों की अनचिछा मुख्य रूप से जनसंख्या दबाव और वैकल्पिक आजीविका प्रणालियों की कमी के कारण है।
 - बाढ़ के मैदानों के संबंध में नयिमों को लागू करने और इन्हें लागू करने के प्रतराज्यों की उदासीन प्रतकिरिया के चलते बाढ़ क्षेत्रों के अतकिरण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जसिमें कभी-कभी अधकृत और नगर नयोजन अधिकारियों द्वारा वधिवित अनुमोदति अतकिरण के मामले देखने को मिलते हैं।

संबंधति संवैधानिकि प्रावधान और अन्य उपाय:

- सूची II (राज्य सूची) की प्रवषिटि 17 के रूप में जल नकिसी और तटबंधों/बाँधों को शामिल करने के आधार पर "अंतर-राज्यीय नदियों एवं नदी के वनियमन और वकिसा" के मामले को छोड़कर, बाढ़ नयितरण कार्य राज्य सरकार के दायरे में आता है। 'घाटियों', का उल्लेख सूची I (संघ सूची) की प्रवषिटि 56 में कया गया है।
 - फ्लड-प्लेन ज़ोनगि राज्य सरकार के दायरे में है क्योंकि यह नदी के कनारे की भूमि से संबंधति है और सूची II की प्रवषिटि 18 के तहत भूमि राज्य का वषिय है।
 - केंद्र सरकार की भूमिका केवल परामर्श देने तथा दशिा-नरिदेश के नरिधारण तक ही सीमति हो सकती है।
- संवधान में शामिल [सातवीं अनुसूची](#) की तीन वधायी सूचियों में से कसी में भी बाढ़ नयितरण और शमन (Flood Control and Mitigation) का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं कया गया है।
- वर्ष 2008 में [राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधकिरण](#) (National Disaster Management Authority- NDMA) ने बाढ़ को नयितरति करने के लिये एक महत्वपूर्ण "गैर-संरचनात्मक उपाय" के रूप में बाढ़ के मैदान क्षेत्र के लिये राज्यों को दशिा-नरिदेश जारी कयि हैं।
- इसने सुझाव दयि कयि कि ऐसे क्षेत्र जहाँ 10 वर्षों में बाढ़ की आवृत्ति के कारण प्रभावति होने की संभावना है, उन क्षेत्रों को पार्कों, उद्यानों जैसे हरे क्षेत्रों के रूप में आरक्षति कया जाना चाहयि तथा इन क्षेत्रों में कंक्रीट संरचनाओं (Concrete Structures) की अनुमति नहीं दी जानी चाहयि।
- इसमें बाढ़ के अन्य क्षेत्रों के बारे में भी बात की गई जैसे- 25 साल की अवधि में बाढ़ की आवृत्ति वाले क्षेत्रों में राज्यों को उन क्षेत्र-वशिषिटि योजना बनाने के लिये कहा गया।

आगे की राह:

- चूँकि बाढ़ से हर साल जान-माल की बड़ी क्षति होती है, इसलिये समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक दीर्घकालिक योजना तैयार करें जो बाढ़ को नियंत्रित करने हेतु तटबंधों के निर्माण तथा ड्रेजिंग जैसे उपायों से बढ़कर हो।
- एक एकीकृत बेसिन प्रबंधन योजना (Integrated Basin Management Plan) की आवश्यकता है जो सभी नदी-बेसिन साझा करने वाले देशों के साथ-साथ भारतीय राज्यों को भी जोड़े।

स्रोत: पी.आई.बी.

भारत में मातृ मृत्यु दर

प्रलिमिंस के लिये:

मातृ मृत्यु अनुपात, भारत का रजिस्ट्रार जनरल, वशिव स्वास्थ्य संगठन

मेन्स के लिये:

महिलाओं से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, मातृ मृत्यु अनुपात से संबंधित पहलें।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (Office of the Registrar General's Sample Registration System-SRS) के कार्यालय ने भारत में वर्ष 2017-19 में **मातृ मृत्यु दर** (Maternal Mortality Ratio-MMR) पर एक वशिष बुलेटिन जारी किया है।

- **वशिव स्वास्थ्य संगठन** के अनुसार, गर्भवती होने पर या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से हुई किसी महिला की मृत्यु को मातृ मृत्यु में शामिल किया जाता है।
- प्रती एक लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर (MMR) कहते हैं।

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया:

- यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- जनसंख्या की गणना करने और देश में मृत्यु और जन्म के पंजीकरण के कार्यान्वयन के अलावा यह नमूना पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System-SRS) का उपयोग करके प्रजनन व मृत्यु दर के संबंध में अनुमान प्रस्तुत करता है।
- SRS देश का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण है जिसमें अन्य संकेतक राष्ट्रीय प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से मातृ मृत्यु दर का प्रत्यक्ष अनुमान प्रदान करते हैं।
- **वर्बल ऑटोप्सी (Verbal Autopsy-VA)** उपकरणों को नियमित आधार पर SRS के तहत दर्ज मौतों के लिये प्रबंधित किया जाता है, ताकि देश में एक वशिषि्ट कारण से होने वाली मृत्यु दर का पता लगाया जा सके।

MMR को लेकर भारत की स्थिति?

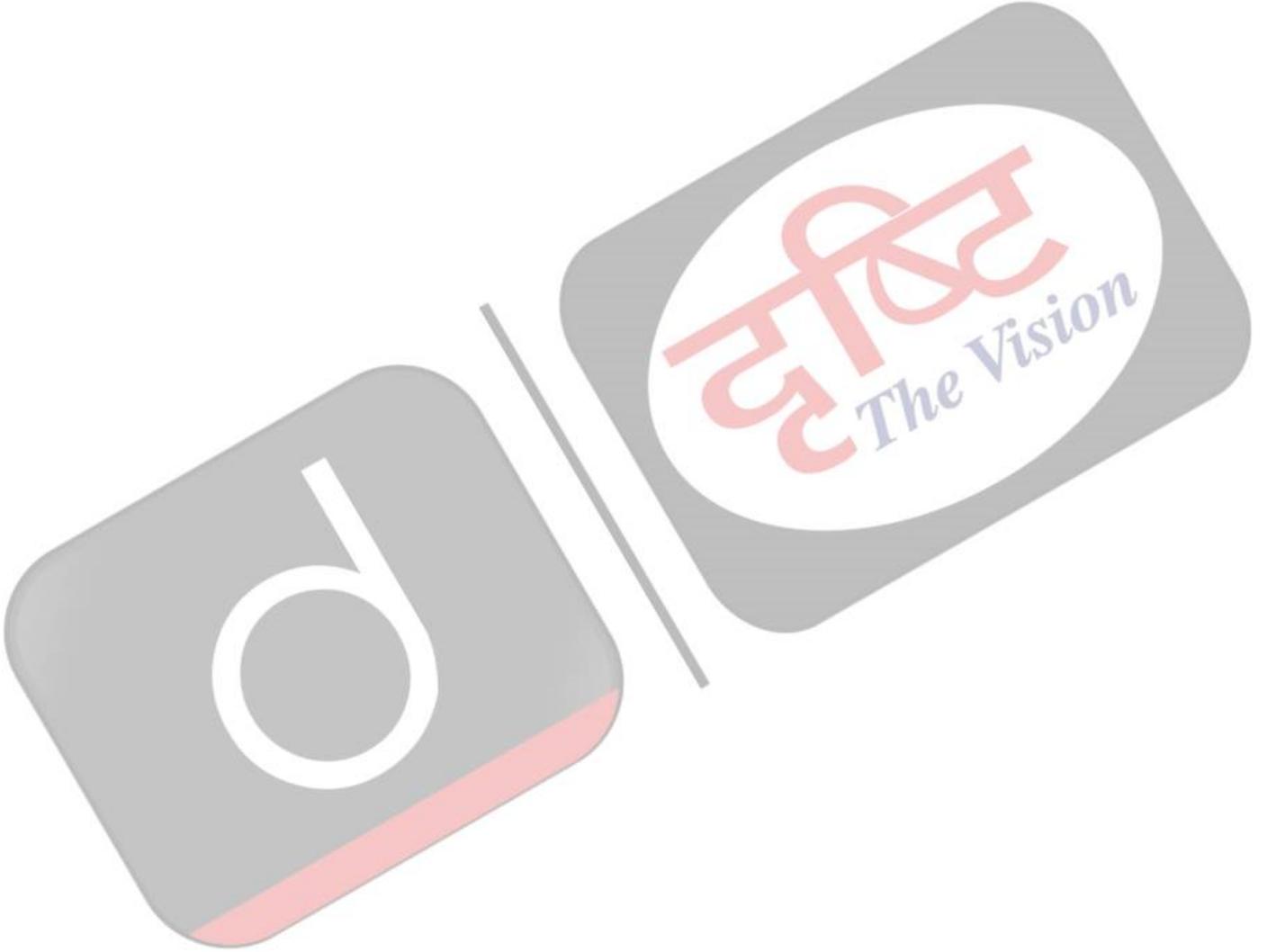
- भारत के मातृ मृत्यु दर में 10 अंक की गिरावट आई है। यह वर्ष 2016-18 के 113 से घटकर वर्ष 2017-18 में 103 (8.8% गिरावट) हो गई है।
- देश में MMR में वर्ष 2014-2016 में 130, वर्ष 2015-17 में 122, वर्ष 2016-18 में 113 और वर्ष 2017-19 में 103 में उत्तरोत्तर कमी देखी गई।
 - भारत वर्ष 2020 तक 100/लाख जीवित जन्मों के **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP)** के लक्ष्य को प्राप्त करने के काफी करीब था और निश्चित रूप से वर्ष 2030 तक 70/लाख जीवित जन्मों के संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर था।
- कई विकसित देशों ने सफलतापूर्वक MMR को एकल अंकों में ला दिया है। इटली, नॉर्वे, पोलैंड और बेलारूस में दो का न्यूनतम MMR है, जबकि

जर्मनी और यूके दोनों में यह सात है, कनाडा में 10 और अमेरिका में 19 है।

- भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों- नेपाल (186), बांग्लादेश (173) और पाकस्तान (140)- का MMR अधिक है। हालाँकि, चीन और श्रीलंका क्रमशः 18.3 व 36 MMR के साथ काफी बेहतर स्थिति में हैं।

राज्य-वशिष्ट आँकड़े:

- सतत विकास लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या अब पाँच से बढ़कर सात हो गई है, ये हैं- केरल (30), महाराष्ट्र (38), तेलंगाना (56), तमिलनाडु (58), आंध्र प्रदेश (58), झारखंड (61) और गुजरात (70)।
 - केरल ने सबसे कम एमएमआर दर्ज किया है जो केरल को राष्ट्रीय एमएमआर 103 से आगे रखता है।
 - केरल के मातृ मृत्यु दर में 12 अंक की गिरावट आई है। पछिले SRS बुलेटिन (2015-17) ने राज्य के MMR को 42 के स्तर पर रखा था, जसिे बाद में समायोजति कर 43 कर दिया गया था।
- अब नौ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा नरिधारति एमएमआर लक्ष्य को हासिल कर लिया है, जसिमें उपरोक्त सात और कर्नाटक (83) एवं हरियाणा (96) शामिल हैं।
- उत्तराखंड (101), पश्चिम बंगाल (109), पंजाब (114), बिहार (130), ओडिशा (136) और राजस्थान (141) में एमएमआर 100-150 के बीच है, जबकि छत्तीसगढ़ (160), मध्य प्रदेश (163), उत्तर प्रदेश (167) तथा असम (205) का एमएमआर 150 से ऊपर है।



कृष्ण संबंधित सरकारी पहलें:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशिन के तहत संस्थागत प्रसव के लिये नकद सहायता प्रदान करने हेतु [जननी सुरक्षा योजना](#)।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की सुनिश्चिता, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल के लिये एक निश्चिता तिथि तय की गई है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान और लक्ष्य दशान-नरिदेश।

आगे की राह

- किसी क्षेत्र की मातृ मृत्यु दर उस क्षेत्र में महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का एक पैमाना है।
- WHO पहले ही मातृ मृत्यु दर को कम करने के भारत के प्रयासों की सराहना कर चुका है। भारत को उच्च एमएमआर वाले राज्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

स्रोत: द हट्टू

चकितिसा और कल्याण पर्यटन हेतु राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप

प्रलिस के लिये:

मेडिकल वीजा, चकितिसा एवं कल्याण पर्यटन।

मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप, चकितिसा एवं कल्याण पर्यटन हेतु राष्ट्रीय रणनीति तथा रोडमैप, एक चकितिसा एवं कल्याण पर्यटन स्थल के रूप में भारत की स्थिति।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने चकितिसा एवं कल्याण पर्यटन हेतु राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार किया है।

- इस नीति के तहत भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल (MVT) और वेलनेस डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

चकितिसा और कल्याण पर्यटन का अर्थ:

- चकितिसा और कल्याण पर्यटन को 'चकितिसा हस्तक्षेप के माध्यम से स्वास्थ्य को बनाए रखने, उसमें सुधार या बहाल करने के उद्देश्य से गंतव्य क्षेत्र में कम-से-कम एक रात ठहरने वाले वदेशी पर्यटक की यात्रा और मेज़बानी से संबंधित गतिविधियों' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

रोडमैप के प्रमुख बट्टु:

- मशिन:** भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल (MVT) और वेलनेस डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों तथा नजी क्षेत्र के मंत्रालयों के बीच एक मज़बूत ढाँचा और तालमेल बनाना।
- नई एजेंसी:** पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय चकितिसा और कल्याण पर्यटन बोर्ड बनाया जाएगा।
 - यह स्वास्थ्य एवं चकितिसा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिये एक समर्पित संस्थागत ढाँचा प्रदान करेगा।
- प्रमुख रणनीतिक स्तंभ:** रणनीति के तहत निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों की पहचान की गई है:
 - भारत के लिये एक वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में एक ब्रांड विकसित करना।
 - चकितिसा और स्वास्थ्य पर्यटन के लिये पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना।
 - ऑनलाइन MVT पोर्टल स्थापित करके डिजिटलीकरण को सक्षम करना।
 - MVT के लिये पहुँच में वृद्धि।
 - वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देना।
 - शासन और संस्थागत ढाँचा।

भारत में चिकित्सा पर्यटन का SWOT विश्लेषण

शक्तियाँ-S	<ul style="list-style-type: none"> ■ भारत में विश्व स्तरीय डॉक्टर और अस्पताल हैं। ■ उपचार की लागत स्रोत बाजारों में भी लागत का ही एक भाग है। ■ पश्चिम में पर्यटन स्थल के रूप में भारत की बढ़ती लोकप्रियता। <ul style="list-style-type: none"> ○ भारत मेडिकल वैल्यू ट्रैवलर को पर्यटन स्थलों की यात्रा के साथ उपचार के संयोजन के लिये पर्यटन के कई अवसर प्रदान करता है। ■ वेस्टर्न मेडिसिन की विशेषज्ञता के साथ-साथ ईस्टर्न हेल्थकेयर वज़िडम। <ul style="list-style-type: none"> ○ ईस्टर्न: पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा जैसे-योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा। ○ वेस्टर्न: एलोपैथी ■ फास्ट ट्रैक नयिकृतियाँ।
कमियाँ-W	<ul style="list-style-type: none"> ■ असंगति MVT फ्रेमवर्क: MVT क्षेत्र को नयित्तरति करने के लिये कोई नयिम नहीं है, जिससे इस क्षेत्र की असंगति प्रकृति और सेवाओं की गुणवत्ता की नगिरानी संबंधी कमी रह जाती है। ■ चिकित्सा संबंधी मूल्यों का नेतृत्व करने के लिये एक नोडल नकियाय का अभाव। ■ MVT गंतव्य के रूप में भारत के लिये कोई अभियान नहीं। ■ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्पतालों के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) मान्यता के बारे में जागरूकता की कमी। ■ अस्पतालों में समान मूल्य निर्धारण नीतियों का अभाव। ■ भारत के संबंध में एक अस्वच्छ देश के रूप में पश्चिमी धारणा।
अवसर-O	<ul style="list-style-type: none"> ■ उम्रदराज आबादी वाले देशों से मांग। ■ स्वास्थ्य और वैकल्पिक इलाज की मांग। ■ वकिसति देशों में लंबी प्रतीक्षा अवधि। ■ अवकिसति चिकित्सा सुवधियों वाले देशों से मांग। ■ भारत का एक वशाल प्रवासी जनसमूह है और वे चिकित्सा उपचार के साथ अपनी भारत यात्रा को जोड़ सकते हैं। ■ बेहतर कनेक्टिविटी।
खतरे-T	<ul style="list-style-type: none"> ■ क्षेत्रीय प्रतियोगिता। ■ अंतरराष्ट्रीय मान्यता का अभाव। ■ वदिशी चिकित्सा देखभाल बीमाकर्त्ता द्वारा कवर नहीं की जाती है। ■ बचौलियों द्वारा शोषण।

चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये उठाए गए कदम:

- 'अतुल्य भारत' ब्रांड लाइन के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा वदिशों में महत्त्वपूर्ण और संभावित बाजारों में वैश्विक प्रटि, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान (global print, electronic and online media campaigns) को जारी किया गया है।
- 'मेडिकल वीज़ा' (Medical Visa) पेश किया गया है, जो चिकित्सा उपचार हेतु भारत आने वाले वदिशी यात्रियों को वशिष्ट उद्देश्यों के लिये दिया जा सकता है।
 - 156 देशों के लिये 'ई-मेडिकल वीज़ा' (E- Medical Visa) और 'ई-मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा' (E-Medical Attendant Visa) भी शुरू किया गए हैं।
- पर्यटन मंत्रालय चिकित्सा/पर्यटन गतिविधियों में भाग लेने के लिये 'अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड' (National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers- NABH) द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं को बाजार विकास सहायता योजना (Market Development Assistance Scheme) के तहत वत्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय की अन्य प्रमुख योजनाएँ:

- [प्रतषिठति पर्यटक स्थल' पहल](#)
- [देखो अपना देश](#)
- [प्रसाद योजना](#)
- [सवदेश दरशन योजना](#)

आगे की राह

- 'एक भारत एक पर्यटन' दृष्टिकोण: पर्यटन के क्षेत्र में कई मंत्रालयों की सहभागिता है जो कई राज्यों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः इस प्रकार केंद्र और अन्य राज्यों के साथ सामूहिक प्रयासों व सहयोग की आवश्यकता होती है।
- पर्यटन की सुगमता को बढ़ावा देना: वास्तव में एक नरिबाध पर्यटक परविहन अनुभव सुनिश्चित करने के लिये हमें सभी अंतरराज्यीय सड़क करों को मानकीकृत करने और उन्हें एक ही बट्टि पर देय बनाने की आवश्यकता है जो व्यवसाय को आसान बनाने हेतु सुविधा प्रदान करेगा।

स्रोत: पी.आई.बी.

सूक्ष्म वित्तीय ऋणों के लिये आरबीआई का नयामक ढाँचा

प्रलिस के लिये:

भारतीय रज़िर्व बैंक, लघु वित्त बैंक, गैर-सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, माइक्रोफाइनेंस संस्थान

मेन्स के लिये:

माइक्रोफाइनेंस ऋण और इसके लाभों के लिये आरबीआई का नयामक ढाँचा, माइक्रोफाइनेंस संस्थान और इसके कार्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) को उन ब्याज दरों को नरिधारित करने की स्वतंत्रता दी, जो वे उधारकर्त्ताओं से वसूलते हैं, तथा यह चेतावनी भी दी है कि दरें अधिक नहीं होनी चाहिये।

- ये दशा-नरिदेश 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे।
- इससे पहले वर्ष 2021 में RBI ने MFI पर ब्याज दर कैप को उठाने का प्रस्ताव रखा था।

दशा-नरिदेशों की मुख्य वशिषताएँ:

- **माइक्रोफाइनेंस ऋण की परभाषा:**
 - 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिये गए संपारशवकि-मुक्त ऋण को इंगति करने हेतु आरबीआई ने माइक्रोफाइनेंस ऋण की परभाषा को संशोधित किये।
 - इससे पहले ऊपरी सीमा ग्रामीण कर्जदारों के लिये 1.2 लाख रुपए और शहरी कर्जदारों के लिये 2 लाख रुपए थी।
- **वनियिमति संस्थाओं के लिये:**
 - संशोधित मानदंडों के अनुसार, वनियिमति संस्थाओं (आरई) को माइक्रोफाइनेंस ऋणों के मूल्य नरिधारण, ब्याज दर की उच्चतम सीमा और माइक्रोफाइनेंस ऋणों पर लागू होने वाले अन्य सभी शुल्कों के संबंध में एक बोर्ड-अनुमोदित नीति बनानी चाहिये।
 - प्रत्येक वनियिमति संस्था को एक मानकीकृत, सरलीकृत फ़ैकटशीट में संभावित उधारकर्त्ता को मूल्य नरिधारण संबंधी जानकारी का खुलासा करना होगा।
- **माइक्रोफाइनेंस ऋण पर जुरमाना:**
 - माइक्रोफाइनेंस ऋणों पर कोई पूरव भुगतान दंड नहीं होगा।
 - वलिंबति भुगतान के लिये जुरमाना, यद कोई हो तो वह अतदिय राश पिर लागू होगा न क संपूरण ऋण राश पिर।
 - ब्याज दर या कसिी अन्य शुल्क में कोई भी परविरतन होने पर उधारकर्त्ता को अग्रमि रूप से सूचित किया जाएगा और ये परविरतन केवल संभावित रूप से प्रभावी होंगे।
- **ऋणों की वसूली:**
 - RE को पुनर्भुगतान से संबंधित कठनिाइयों का सामना करने वाले उधारकर्त्ताओं की पहचान करने, ऐसे उधारकर्त्ताओं के साथ जुड़ाव और उन्हें उपलब्ध सहायता के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक तंत्र स्थापित करना होगा।
 - यह तंत्र उचित नोटसि और प्राधिकरण सुनिश्चित करने हेतु RE वसूली प्रक्रिया शुरू करते समय उधारकर्त्ता को वसूली एजेंटों (Recovery Agents) का वविरण प्रदान करेगा।

दशा-नरिदेशों की प्रयोज्यता:

- **भुगतान बैंकों** को छोड़कर सभी **वाणजियकि बैंक** (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)।
- सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक।
- सभी **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियिं** (माइक्रोफाइनेंस संस्थान और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियिं सहित)।

वर्षों के प्रश्न:

भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिये ऋण के वितरण में नमिनलखिति में से कसिका हसिसा सबसे अधकि है? (2011)

- (a) वाणजियकि बैंक
- (b) सहकारी बैंक
- (c) कषेत्रीय ग्रामीण बैंक
- (d) माइक्रोफाइनेंस संस्थान

उत्तर: (a)

होने वाले लाभ:

- **बाज़ार का वसितार:** 3 लाख रुपए की आय कैप में संशोधन से बाज़ार के अवसर का वसितार होगा और इंटररेस्ट रेट कैप (Interest Rate Cap) को समाप्त करने से जोखमि आधारति बीमा को बढ़ावा मलैगा ।
- **स्वस्थ प्रतसिपरद्धा को बढ़ावा:** यह वभिनिन प्रकार के ऋणदाताओं हेतु नयामक ढाँचे के सामंजस्य द्वारा स्वस्थ प्रतसिपरद्धा को प्रोत्साहति करने और ग्राहकों को उनकी क्रेडिट ज़रूरतों के बारे में एक सूचति वकिल्प नरिमति करने हेतु दीर्घ अवधि में मदद करेगा ।
- **वत्तीय समावेशन:** नया ढाँचा उद्योग को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, बेहतर जोखमि शमन और वत्तीय समावेशन सुनश्चिति करेगा ।
- **एक समान स्तर का नरिमाण:** यह एक समान स्तर को नरिमति करेगा और उधारकर्त्ताओं और ऋणदाताओं दोनों के पास अब वकिल्प होंगे ।
- **ज़रूरतमंदों की मदद:** यह उधारकर्त्ताओं के हतियों की रक्षा करेगा और इस कषेत्र में ज़रूरतमंद उधारकर्त्ताओं की मदद करेगा ।

माइक्रोफाइनेंस संस्थान क्या है?

- माइक्रोफाइनेंस संस्थान एक ऐसा संगठन है, जो अल्प आय वाली आबादी को वत्तीय सेवाएँ प्रदान करता है ।
 - इन सेवाओं में सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म बचत और सूक्ष्म बीमा आदि शामिल हैं ।
- MFI वत्तीय कंपनयिों उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करती हैं, जनिकी बैंकिंग सुवधिओं तक पहुँच नहीं होती है ।
- ज़्यादातर मामलों में ब्याज दरें सामान्य बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली दरों से कम होती हैं । अतः कुछ लोगों ने इन माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं पर गरीब लोगों के पैसे में हेरफेर करके लाभ कमाने का आरोप लगाया है ।
- पछिले कुछ दशकों में माइक्रोफाइनेंस कषेत्र तेज़ी से बढ़ा है और वर्तमान में इनके पास भारत की गरीब आबादी के लगभग 102 मिलियन खाते (बैंकों और लघु वत्ति बैंकों सहति) हैं ।
- गरीब लोगों के लिये वभिनिन प्रकार के वत्तीय सेवा प्रदाता उभरे हैं, जसिमें [गैर-सरकारी संगठन](#) (NGO), [सहकारति](#), [स्व-सहायता समूह](#), क्रेडिट यूनयिन, सामुदायकि-आधारति वकिस संस्थान, वाणजियकि और राज्य बैंक, बीमा तथा क्रेडिट कार्ड कंपनयिों, डाकघर आदि शामिल हैं ।
- भारत में गैर-बैंकिंग वत्तीय कंपनयिों और MFIs का नयिमन रज़िर्व बैंक के गैर-बैंकिंग वत्तीय कंपनी -माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (रज़िर्व बैंक) नरिदेश, 2011 द्वारा कयिा जाता है ।

वर्षों के प्रश्न

माइक्रोफाइनेंस के तहत नमिन आय वर्ग के लोगों के लिये वत्तीय सेवाओं का प्रावधान है । इसमें उपभोक्ता एवं स्वरोज़गार दोनों शामिल हैं । माइक्रोफाइनेंस के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ हैं:

1. क्रेडिट की सुवधि
2. बचत की सुवधि
3. बीमा सुवधि
4. फंड ट्रांसफर की सुवधि

नीचे दयि गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

स्रोत: द हट्टि

भारत में रोहंगिया मुस्लिमि

प्रलिमिस के लयि:

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी, रोहंगिया मुस्लिमि, संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सारक), 1951 का शरणार्थी सम्मेलन और इसका 1967 का प्रोटोकॉल ।

मेन्स के लयि:

भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित सुरक्षा चिंता ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रीय जाँच एजेंसी](#) ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है जो कथित रूप से रोहंगिया मुस्लिमि की भारतीय क्षेत्र में अवैध तस्करी में शामिल एक सडिकेट का हिस्सा थे ।



प्रमुख बदि

रोहगिया मुसलमि:

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा रोहगिया मुसलमानों को दुनिया में सबसे अधिक सताए गए अल्पसंख्यक के रूप में वर्णित किया गया है।
- वर्ष 2017 में ये म्यांमार सेना की कथित कार्रवाई से बचने के लिये अपने घर छोड़कर भाग गए थे।
- दशकों से बौद्ध-बहुल देश म्यांमार में भेदभाव और हिंसा से बचने के लिये अल्पसंख्यक रोहगिया मुसलमान पड़ोसी देश बांग्लादेश और भारत सहित अन्य देशों में भाग गए।

भारत की सुरक्षा से संबंधी मुद्दे और चर्चाएँ

- **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा:** भारत में रोहगियाओं के अवैध अप्रवास की नरिंतरता और उनके भारत में रहने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और यह गंभीर सुरक्षा खतरे पैदा करता है।
- **हत्तों का टकराव:** यह उन क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के हत्तों को प्रभावित करता है जो बड़े पैमाने पर अप्रवासियों के अवैध रूप से प्रवेश का सामना करते हैं।
- **राजनीतिक अस्थिरता:** यह राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ाता है जब नेता राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिये अभिजात वर्ग द्वारा प्रवासियों के खिलाफ देश के नागरिकों की धारणा को लामबंद करना शुरू करते हैं।
- **उग्रवाद का उदय:** अवैध प्रवासियों के रूप में माने जाने वाले मुसलमिों के खिलाफ लगातार होने वाले हमलों ने कट्टरपंथ का मार्ग प्रशस्त किया है।
- **मानव तस्करी:** हाल के दशकों में सीमाओं पर महिलाओं और मानव तस्करी की घटनाओं में काफी वृद्धि देखी गई है।
- **कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी:** अवैध और राष्ट्रवैरोधी गतिविधियों में लपित अवैध प्रवासियों द्वारा देश की कानून व्यवस्था और अखंडता को कमजोर किया जाता है।

‘राष्ट्रीय जाँच एजेंसी’ क्या है?

- इसका गठन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था। यह ऐसे अपराधों की जाँच करने और मुकदमा चलाने हेतु एक केंद्रीय एजेंसी है, जो अपराध हैं:
 - भारत की संप्रभुता, सुरक्षा एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, वदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करने वाले अपराध।
 - परमाणु और परमाणु प्रतष्ठानों के वरिद्ध अपराध।
 - उच्च गुणवत्तायुक्त नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी।
- यह अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों, अभिसमयों (Conventions) और संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रस्तावों का कार्यान्वयन करती है।
- इसका उद्देश्य भारत में आतंकवाद का मुकाबला करना भी है।
- इसका मुख्यालय नई दलिली में है।

आगे की राह

- **शरणार्थी संरक्षण ढाँचे की आवश्यकता:** वर्ष 1951 के शरणार्थी अभिसमय और इसके 1967 के प्रोटोकॉल का एक पक्ष नहीं होने के बावजूद भारत दुनिया में शरणार्थियों के सबसे बड़े प्राप्तकर्त्ताओं में से एक रहा है।
 - इसलिये यदि भारत में शरणार्थियों के संबंध में घरेलू कानून होता, तो यह पड़ोस में किसी भी दमनकारी सरकार को उनकी आबादी को सताने और उन्हें भारत में पलायन करने से रोक सकता था।
- **शरणार्थियों पर सार्क ढाँचा:** भारत को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) में अन्य देशों को सार्क सम्मेलन या शरणार्थियों पर घोषणा के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस